



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 299] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 1984/आषाढ़ 7, 1906
No. 299] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1984/ASADHA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

वर्ष की अवधि के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत
किया था।

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 1984

का० आ० 470(अ)/18कक/आई० डी० आर० ए०/
84:—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक
विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 134 (अ)/
18कक/आई० डी० आर० ए०/79, तारीख 13 मार्च, 1979
द्वारा यथा उपांतरित आदेश सं० का० आ० 529(अ)/
18कक/आई० डी० आर० ए०/74, तारीख 6 सितम्बर,
1474 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा
गया है) सचिव, वन्द रुग्ण उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल
सरकार को (जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण
विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार कहा गया है) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् उक्त अधिकृत व्यक्ति कहा गया है) सैमस
इंडिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरमपुर,
पश्चिमी बंगाल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक
उपक्रम कहा गया है) तारीख 6 सितम्बर, 1974 से पांच

और केन्द्रीय सरकार की यह राय थी कि लोकहित में
यह समीचीन है कि उक्त अधिसूचित आदेश को उपयुक्त
पांच वर्ष के समाप्त होने के बाद प्रभावी बना रहना चाहिए,
और उसमें 30 जून, 1984 तक की, जिसके अन्तर्गत वह
तारीख भी है, अतिरिक्त अवधि के लिये इसे जारी रखने
के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किये थे, (देखिए
भारत सरकार के औद्योगिक विकास विभाग सं० का० आ०
512 (अ)/18कक/आई० डी० आर० ए०/79, तारीख
4 सितम्बर, 1979, सं० का० आ० 749 (अ)/18कक/
आई० डी० आर० ए०/80, तारीख 5 सितम्बर, 1980,
और सं० का० आ० 684(अ)/18कक/आई० डी० आर०
ए०/81, तारीख 4 सितम्बर, 1981, सं० का० आ०
125(अ)/18कक/आई० डी० आर० ए०/82, तारीख
5 मार्च, 1982, सं० का० आ० 648(अ)/18कक/आई०
डी० आर० ए०/82, तारीख 4 सितम्बर, 1982, सं०
का० आ० 158(अ)/18कक/आई० डी० आर० ए०/83,

तारीख 4 मार्च, 1983, सं० का० आ० 386 (अ)/18कक/आई० डी० आर० ए०/83, तारीख 31 मई, 1983 तथा सं० का० आ० 937 (अ)/18कक/आई० डी० आर० ए०/83, तारीख 29 दिसम्बर, 1983;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा 31 दिसम्बर, 1984 तक की और अवधि के लिए जारी रखा जाये,

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 दिसम्बर, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है की और अवधि लिये प्रभावी रहेगा।

[फा० सं० 2(14)/80-सी० यू० एस०]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 28th June, 1984

S.O. 470(E)|18AA|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 529(E)|18AA|IDRA|74, dated the 6th September, 1974 as modified by the Order No. S.O. 134(E)|18AA|IDRA|79, dated the 13th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of Messrs India Belating and Cotton Mills Limited, Serampore, West Bengal (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for

a period of five years from the 6th September, 1974 ;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1984 (vide Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development)).

Nos. S.O. 512(E)|18AA|IDRA|79, dated the 4th September, 1979,

S.O. 749(E)|18AA|IDRA|80, dated the 5th September, 1980,

S.O. 684(E)|18AA|IDRA|81, dated the 4th September, 1981,

S.O. 125(E)|18AA|IDRA|82, dated the 5th March, 1982,

S.O. 648(E)|18AA|IDRA|82, dated the 4th September, 1982,

S.O. 158(E)|18AA|IDRA|83, dated the 4th March, 1983,

S.O. 386(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st May, 1983 and

S.O. 937(E)|18AA|IDRA|83, dated the 29th December, 1983;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised person should continue for a further period upto 31st December, 1984.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st December, 1984.

(File No. 2(14)|80-CUS)

A. P. Jt. Secy.